SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (Madhya Pradesh): Sir,...*(Interruptions)*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, Mr. Thirunavukkarasar, please co-operate; it is not good...*(Interruptions)*... What extra can you say?

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR: Sir, they are disturbed...*(Interruptions)*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri Tariq Anwar.

Floods in Bihar

श्री तारिक अनवर(महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, बिहार में जो जानलेवा बाढ़ आई है, उसकी तरफ मैं इस सदन का और केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस बात की जानकारी सभी लोगों को पत्रों के द्वारा और अखबारों के द्वारा मिली है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी पर जो बांध है, उसके टूटने के कारण आई बाढ़ से उस जिले के लगभग 200 गाँव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

उपसभापति महोदय, वहाँ रुन्नीसैदपुर प्रखंड में एक गाँव तिलकराजपुर है, उसके पास यह embankment या बाँध था, जिसके टूटने से यह स्थिति बनी है। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि शुक्रवार को जिला प्रशासन के लोग और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स उस स्थान पर गए थे और यह कहा था कि इस बांध को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके एक दिन बाद, यानी शनिवार को, उसी स्थल पर वह बांध टूट गया। आपको यह जानकर भी ताज्जुब होगा कि पिछले वर्ष राज्य सरकार के द्वारा उस बांध की पूरी तरह से मरम्मत भी कराई गई थी। वह मरम्मत किस तरह की थी कि वह बांध टूट गई और जिसकी वजह से आज एक लाख से ज्यादा लोग उससे प्रभावित हैं? इससे सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं, बल्कि उससे adjoining districts, जैसे दरभंगा और मुजफ्फरपुर, के भी कई गाँव प्रभावित हुए हैं। यह भी ताज्जुब की बात है कि बाढ़ आने के 24 घंटे बाद भी वहाँ अभी भी लोगों तक relief का साधन नहीं पहुँचा है। यह बात सभी अखबारों में छपी है कि अभी भी वहाँ लोग embankment में हैं, अभी भी वहाँ लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पिछले साल जो बाढ़ आयी थी, जो भयानक बाढ़ आयी थी, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गये थे और हजारों लोगों को नुकसान हुआ था ...(**व्यवधान**)... बिहार सरकार ने उससे कोई सीख नहीं ली और इस साल भी उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ...(**व्यवधान**)

SHRI N.K. SINGH (Bihar): Sir, this is not fair. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Whatever he is saying is his view. ...*(Interruptions)*

SHRI N.K. SINGH: *

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): *

डा. सी.पी. ठाकुर (बिहार): *

श्री उपसभापति: देखिये, जब आप इश्यू उठाते हैं तो वह सही है और जब दूसरे बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं देते हैं। यह क्या बात है? ...(**व्यवधान**)... यह उनका विचार है ...(**व्यवधान**)... आप क्यों...(**व्यवधान**)... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record.

SHRI N.K. SINGH: *

श्री तारिक अनवर: सर, बिहार सरकार द्वारा पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): *

श्री तारिक अनवर: मैंने जैसा पहले बताया, बिहार सरकार का यह दावा था कि embankment नहीं टूटेगा और उसके बाद भी वह embankment टूटा है और पिछले वर्ष से कोई सीख नहीं ली गई।

* Not recorded.

...(**समय की घंटी**)... पिछले वर्ष इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसमें केवल इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गयी।...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: समय हो गया। ...(**व्यवधान**)... Mr. Anwar, it is not going on record.

श्री तारिक अनवर: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform the House that the Constitution (109th) Amendment Bill is being taken up in the House today for consideration and passing. The Bill has to be passed by special majority under article 368 of the Constitution of India. To enable the Members to be present at the time of division on various stages of the Bill, it is informed that the first division on the Bill will be called at around 2.05 p.m. Now, the Legislative Business. The Judges (Declaration of Assets and Liabilities) Bill, 2009. Shri M. Veerappa Moily.

————————

GOVERNMENT BILLS

The Judges (Declaration of Assets and Liabilities) Bill, 2009

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, I have given a notice. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. Yes. ...*(Interruptions)*... Mr. Minister, in introduction, there are notices for objection; notices to oppose the introduction of the Bill. ...*(Interruptions)*... The Leader of Opposition, Shri Arun Jaitley.

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, the hon. Law Minister has sought to introduce the Judges (Declaration of Assets and Liabilities) Bill, 2009. Sir, I have an objection to the introduction of this Bill. I am conscious of the fact that the introduction of the Bill can be opposed primarily on two grounds, either on the ground of lack of legislative competence or on violation of the Constitution; and the Bill itself being ultra-vires. I have particular objection to clause 6 of the Bill. Sir, clause 6 of the Bill specifically states, and, I am reading clause 6, "notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a declaration made by a Judge to a competent authority shall not be made public or disclosed, and, shall not be called for, or, put into question by any citizen, court or authority, and, save as provided by sub-section 2, no Judge shall be subjected to any enquiry or query in relation to the contents of the declaration by any person."

Sir, earlier, the issue had come up where candidates contesting elections either for Parliament or Assembly were required to file a declaration with regard to their antecedents, criminal cases and education as also their assets and liabilities. The law was clearly laid down by the Supreme Court and the law was based on the understanding of article 19(1)(a) of the Constitution of India, and, on the strength of Freedom of Expression which they said, also includes the Right to Information as far as people are concerned, all persons desirous of

*Not recorded.